

Integrated Goods & Services Tax Act, 2017

Section 6 : Power to grant exemption from tax

- (1) Where the Government is satisfied that it is necessary in the public interest so to do, it may, on the recommendations of the Council, by notification, exempt generally, either absolutely or subject to such conditions as may be specified therein, goods or services or both of any specified description from the whole or any part of the tax leviable thereon with effect from such date as may be specified in such notification.
- (2) Where the Government is satisfied that it is necessary in the public interest so to do, it may, on the recommendations of the Council, by special order in each case, under circumstances of an exceptional nature to be stated in such order, exempt from payment of tax any goods or services or both on which tax is leviable.
- (3) The Government may, if it considers necessary or expedient so to do for the purpose of clarifying the scope or applicability of any notification issued under sub-section (1) or order issued under sub-section (2), insert an Explanation in such notification or order, as the case may be, by notification at any time within one year of issue of the notification under sub-section (1) or order under sub-section (2), and every such *Explanation* shall have effect as if it had always been the part of the first such notification or order, as the case may be.

Explanation—For the purposes of this section, where an exemption in respect of any goods or services or both from the whole or part of the tax leviable thereon has been granted absolutely, the registered person supplying such goods or services or both shall not collect the tax, in excess of the effective rate, on such supply of goods or services or both.

धारा 6 : कर से छूट प्रदान करने की शक्ति

- (1) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, वहां वह, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, साधारणतया या तो आत्यंतिक रूप से या ऐसी शर्तों के अधीन, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी विनिर्दिष्ट प्रकार के माल या सेवा या दोनों को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण कर या उसके भाग से, ऐसी तारीख से, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, छूट प्रदान कर सकेगी।
- (2) जहां सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, वहां वह, परिषद् की सिफारिशों पर प्रत्येक मामले पर विशेष आदेश द्वारा, उस आदेश में कथन की जाने वाली किन्हीं आपवादिक परिस्थितियों में किसी भी माल या सेवा या दोनों पर, जिस पर कर उद्ग्रहणीय है, कर के संदाय से छूट प्रदान कर सकेगी।
- (3) सरकार, यदि उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन जारी आदेश के क्षेत्र या लागू होने को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है, तो उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के जारी किए जाने या उपधारा (2) के अधीन आदेश के एक वर्ष के भीतर किसी भी समय अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना या आदेश में कोई स्पष्टीकरण अंतःस्थापित कर सकेगी और ऐसा प्रत्येक स्पष्टीकरण इस प्रकार प्रभावी होगा, मानो वह सदैव, यथास्थिति, ऐसी पहली अधिसूचना या आदेश का भाग था।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी माल या सेवा या दोनों की बाबत उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण कर या उसके भाग से आत्यंतिक रूप से छूट प्रदान की गई है, वहां ऐसे माल या सेवा या दोनों की पूर्ति करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, माल या सेवा या दोनों ऐसी की पूर्ति पर प्रभावी दर से अधिक कर संगृहीत नहीं करेगा।